देशभर में बनेंगे 25 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे

गडकरी का बड़ा ऐलान- देशभर में बनेंगे 25 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, 6 लाख करोड़ का होगा निवेश

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को पीएचडीसीसीआई के 120वें वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए देश के बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में हो रहे बड़े बदलावों पर प्रकाश डाला.

मंत्री गडकरी ने घोषणा की कि सरकार देशभर में 25 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रही है, जिनकी कुल लंबाई 10,000 किलोमीटर होगी. इन परियोजनाओं में 6 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा. उन्होंने बताया कि रणनीतिक जोजिला सुरंग का 75-80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, जो लद्दाख क्षेत्र और देश के बाकी हिस्सों के बीच सालभर

संपर्क सुनिश्चित करेगा. उन्होंने यह भी कहा कि सड़क परिवहन मंत्रालय अगर अपनी सड़क परियोजनाओं का मुद्रीकरण करता है, तो उसे 15 लाख करोड़ रुपये तक मिल सकते हैं.

ऑटोमोबाइल उद्योग को नंबर 1 बनाने का लक्ष्य- भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र के बारे में बात करते हुए गडकरी ने कहा कि उनका लक्ष्य अगले पांच सालों में भारत के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को दुनिया का नंबर 1 बनाना है. उन्होंने बताया कि जब उन्होंने परिवहन मंत्री का कार्यभार संभाला था, तब इस उद्योग का आकार 14 लाख करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 22 लाख करोड़ रुपये हो गया है. उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र 4 लाख युवाओं को रोजगार देता है और केंद्र तथा राज्य दोनों को सर्वाधिक जीएसटी प्रदान करता है.

स्वच्छ ऊर्जा और जीडीपी पर फोकस- मंत्री ने ईंधन आयात पर भारत की निर्भरता को 22 लाख करोड़ रुपये सालाना का आर्थिक बोझ बताया और कहा कि स्वच्छ ऊर्जा अपनाना देश की प्रगति के लिए आवश्यक है. उन्होंने बताया कि किसानों ने मक्का से एथनॉल उत्पादन करके अतिरिक्त 45,000 करोड़ रुपये की आय प्राप्त की है.

लॉजिस्टिक्स लागत में ऐतिहासिक कमी

गडकरी ने बताया कि एक्सप्रेसवे और आर्थिक गलियारों के निर्माण के कारण देश की लॉजिस्टिक्स लागत 16 प्रतिशत से घटकर 10 प्रतिशत पर आ गई है. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह लागत दिसंबर तक 9 प्रतिशत तक कम हो जाएगी, जिससे भारत विश्व स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेगा. उन्होंने तुलना करते हुए कहा कि चीन में लॉजिस्टिक्स लागत 8 से 10 प्रतिशत, जबकि अमेरिका और यूरोपीय देशों में 12 प्रतिशत है.

भारत-बीपी सहयोग से मिलेगी नई गति

मुंबई हाई फील्ड पुनरुद्धार, रिटेल और बायोगैस परियोजनाओं पर सहयोग जारी

मंत्री ने कहा-प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में मजबूत कदम

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर. केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को बीपी के सीईओ मरे औचिनक्लॉस के साथ ऑनलाइन बातचीत की, जिसे उन्होंने उत्कृष्ट बताया. मरे औचिनक्लॉस, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की दो दिवसीय भारत यात्रा पर उनके साथ आए व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं.

स्टार्मर 100 से अधिक ब्रिटिश व्यापारिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं. केंद्रीय मंत्री पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बीपी का भारत में एनर्जी वैल्यू चेन के क्षेत्र में दीर्घकालिक और व्यापक जुड़ाव है. उन्होंने बताया कि बीपी ओएएलपी राउंड-10 के तहत ब्लॉकों की खोज कर रही है.

यह पहली बार नहीं है जब मंत्री पुरी और औचिनक्लॉस के बीच बातचीत हुई है. इससे पहले, जुलाई में विएना में आयोजित 9वें ओपेक अंतरराष्ट्रीय सेमिनार के दौरान भी दोनों की बैठक हुई थी.

मजबूत होती साझेदारी

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों ने मुंबई हाई फील्ड के पुनरुद्धार के लिए बीपी के साथ साझेदारी की है. इसके अतिरिक्त, दोनों पक्ष रिटेल, नेचुरल गैस और कंप्रेस्ड बायोगैस के क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं. पुरी ने जोर देकर कहा कि यह सहयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में भारत के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण घटक है.

2033 तक तीन गुना होगा सैटकॉम बाज़ार : सिंधिया

भारत बनेगा सैटेलाइट कम्युनिकेशन में ग्लोबल लीडर

भारत ने 20 महीनों में लगाए 4.8 लाख 5जी टावर, 99.9% आबादी जुड़ी

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर. केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घोषणा की है कि भारतीय सैटकॉम बाज़ार 2024 में 4.3 अरब डॉलर मूल्य का है, जिसके 2033 तक तीन गुना बढ़कर 14.8 अरब डॉलर होने की उम्मीद है. यह वृद्धि इस क्षेत्र की अपार आर्थिक और रणनीतिक क्षमता को दर्शाती है.

इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) 2025 कार्यक्रम के दौरान सैटकॉम समिट को संबोधित करते हुए मंत्री सिंधिया ने कहा कि यह क्षेत्र एक क्रांति की दहलीज पर है, जो आकाश में जन्मी है, सैटेलाइट द्वारा संचालित है, लेकिन जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर जीवन को बदलना है.

सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के डिजिटल परिवर्तन पर प्रकाश डाला, जिसमें देश ने केवल 20 महीनों में 4.8 लाख 5जी टावरों के माध्यम से अपनी 99.9 प्रतिशत आबादी को जोड़ा है. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि साहसिक नीतिगत सुधारों और इनोवेशन के प्रति प्रतिबद्धता के साथ भारत सैटेलाइट कम्युनिकेशन में दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है, साथ ही यूनिवर्सल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा.

राष्ट्रीय सुरक्षा और कनेक्टिविटी पर फोकस

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने दो महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं-

नेशनल सैटकॉम मॉनिटरिंग फैसिलिटी- 900 करोड़ रुपये की लागत से इस फैसिलिटी की स्थापना की जाएगी, जिसका उद्देश्य स्पेक्ट्रम एसेट्स की सुरक्षा करना और भारत के सैटेलाइट गेटवे को मजबूत करना है.

डिजिटल भारत निधि मिशन- सरकार ने डिजिटल भारत निधि और यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ चुनौतीपूर्ण इलाकों में स्थित 38,260 दूरदराज के गांवों को जोड़ने का मिशन शुरू किया है.

नवीकरणीय ऊर्जा में भारत ने रचा नया इतिहास : जोशी

भारत ने 125 गीगावाट सौर क्षमता के साथ तीसरा स्थान हासिल किया

पीएम सूर्य घर योजना से 20 लाख परिवारों को मिला सौर लाभ

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर. केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने घोषणा की है कि लगभग 125 गीगावाट सौर क्षमता के साथ भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है.

मंत्री ने कहा कि देश ने निर्धारित समय से पांच वर्ष पहले ही अपने नवीकरणीय ऊर्जा (ऋश्व) लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, और कुल स्थापित बिजली क्षमता में गैर-जीवाश्म संसाधनों की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत के आंकड़े को पार कर गई है.

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का आठवाँ सत्र 27 से 30 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा. यह आयोजन एक सूरज, एक विजन और सौर ऊर्जा के प्रति एक साझा वैश्विक प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाएगा. केंद्रीय मंत्री जोशी ने बताया कि भारत की सफलता केवल संख्याओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्थानीय स्तर पर बड़े बदलाव ला रही है. उन्होंने कहा कि विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा ग्रामीण घरों में रोशनी ला रही है, स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों को शक्ति प्रदान कर रही है और किसानों को नए उपकरण उपलब्ध करा रही है.

प्रमुख योजनाएँ और उपलब्धियाँ

पीएम सूर्य घर- मुफ्त बिजली योजना- इस योजना के तहत 20 लाख से अधिक परिवार सौर ऊर्जा से लाभान्वित हो रहे हैं.

पीएम-कुसुम योजना- इस योजना के तीन घटकों का लक्ष्य 10 गीगावाट के छोटे सोलर प्लांट लगाना, 1.4 मिलियन ऑफ-ग्रिड सोलर पंपों को सहायता देना और 3.5 मिलियन ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है.

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी ने देश की प्रगति पर जोर देते हुए कहा, आज हम सौर ऊर्जा में तीसरे सबसे बड़े, पवन ऊर्जा में चौथे सबसे बड़े और कुल मिलाकर, अब दुनिया में तीसरे सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठान हैं.

> आईएसए के महानिदेशक आशीष खन्ना ने ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी की तेज प्रगति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि तेल को 1,000 गीगावाट तक पहुँचने में 25 वर्ष लगे थे, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा ने इसे केवल दो वर्षों में दोगुना कर दिया है.

चांदी 6,000 रुपये उछली, पहुंची 1.63 लाख प्रति किलो

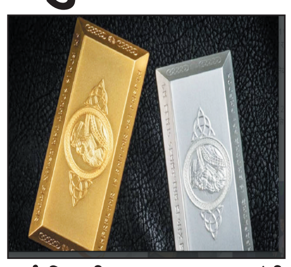

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर. चांदी की कीमत राष्ट्रीय राजधानी में बृहस्पतिवार को 6,000 रुपये की तेजी के साथ 1,63,000 रुपये प्रति किलोग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई.

भू-राजनीतिक, आर्थिक अनिश्चितताओं और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में कटौती के अनुमान के बीच वैश्विक बाजार में सुरक्षित निवेश के रूप में इसकी खरीदारी बढ़ी. चांदी में एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार इतना तेज उछाल आया है. छह अक्टूबर को यह 7,400 रुपये चढ़कर 1,57,400 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई थी.

अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, बुधवार को कारोबार के अंत में चांदी की कीमत 1,57,000 रुपये प्रति किलोग्राम रही. स्थानीय सर्राफा बाजार में, 99.9 प्रतिशत और 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना बृहस्पतिवार को अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर क्रमशः 1,26,600 रुपये और 1,26,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर अपरिवर्तित रहा.

दूरदर्शन पर फिर लौट रहा है 'महाभारत'

मुंबई, 10 अक्टूबर . प्रसार भारती और कलेक्टिव मीडिया नेटवर्क ने संयुक्त रूप से भारत के सबसे प्रतिष्ठित महाकाव्य 'महाभारत' के एआई-संचालित नव-रूपांतरण की घोषणा की है. यह श्रृंखला 25 अक्टूबर 2025 को वेव्स ओटीटी पर डिजिटल प्रीमियर के रूप में प्रदर्शित होगी तथा नवंबर 2025 से हर रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर प्रसारित की जाएगी. यह प्रस्तुति भारत ही नहीं, बल्कि विश्वभर के दर्शकों के लिए वेव्स प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध होगी.

यह साझेदारी भारतीय प्रसारण इतिहास में एक नया अध्याय है, जो प्रसार भारती की विश्वसनीयता और राष्ट्रीय पहुंच को कलेक्टिव मीडिया नेटवर्क की रचनात्मकता एवं अत्याधुनिक तकनीक से जोड़ती है. नवीनतम एआई उपकरणों की सहायता से 'महाभारत' के पात्रों, युद्धभूमियों और भावनात्मक द्वंद्वों को भव्य सिनेमाई रूप में पुनर्जीवित किया गया है. यह परियोजना 'मेक इन इंडिया' और 'डिजिटल इंडिया' की भावना का सशक्त प्रतीक है.

प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा, लॉकडाउन के दौरान 'महाभारत' के पुनः प्रसारण ने यह सिद्ध किया कि ऐसी कथाएँ परिवारों और पीढ़ियों को गहराई से जोड़ती हैं. अब एआई आधारित इस रूपांतरण के माध्यम से दर्शक इसे एक नए, सजीव और आधुनिक रूप में अनुभव करेंगे. यह परंपरा और तकनीक का संगम है. कलेक्टिव आर्टिस्ट्स नेटवर्क के संस्थापक एवं समूह सीईओ विजय सुब्रमण्यम ने कहा, मैं भी उन करोड़ों भारतीयों में से हूँ.

भव्य दिवाली कार्निवल

नईदिल्ली. दिल्ली पर्यटन 11 और 12 अक्टूबर 2025 को दिल्ली हाट जनकपुरी में भव्य दिवाली कार्निवल का आयोजन कर रहा है। इस उत्सव के दौरान निम्नलिखित गतिविधियाँ प्रस्तावित हैं. सुंदर थीम वाला माहौल भोजन, वस्त्र, आभूषण, हस्तशिल्प, हथकरघा आदि के स्टॉल। सांस्कृतिक कार्यक्रम - दास्तान गोई - कहानी कहने का एक पारंपरिक तरीका, मणिपुर राज्य द्वारा लोक प्रस्तुतियाँ, पंजाबी संगीत और नृत्य प्रस्तुतियाँ आदि। रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी और विजेताओं को निम्नानुसार नकद पुरस्कार दिए जाएँगे. प्रथम पुरस्कार 2500/- रुपये, द्वितीय पुरस्कार 2000/- रुपये, तृतीय पुरस्कार 1500/- रुपये, 500/- रुपये के तीन सांत्वना पुरस्कार.

विनिर्माण क्षेत्र में मज़बूत वृद्धि के संकेत

फिक्की सर्वे में 87% कंपनियों ने उत्पादन बढ़ने या स्थिर रहने की बात कही

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर. उद्योग मंडल फिक्की के नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार, देश का विनिर्माण क्षेत्र लगातार मज़बूत वृद्धि और विस्तार की राह पर है. सर्वेक्षण में शामिल 87 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सितंबर तिमाही में उत्पादन स्तर में वृद्धि या स्थिरता दर्ज की है. यह आंकड़ा अप्रैल-जून तिमाही के 77 प्रतिशत के मुकाबले विनिर्माण गतिविधियों में महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाता है.

सर्वे रिपोर्ट बताती है कि पिछले वर्ष की तुलना में जुलाई-सितंबर 2025-26 तिमाही के दौरान उत्पादन और मांग दोनों में सुधार के संकेत मिले हैं.

मांग में आशावाद और लागत का दबाव

फिक्की के अनुसार, घरेलू मांग में भी आशावाद झलक रहा है. लगभग 83 प्रतिशत उत्तरदाता जुलाई-सितंबर तिमाही में ऑर्डर बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं, जिसका एक अहम कारण हाल ही में घोषित जीएसटी दर कटौती हो सकती है. हालांकि, उत्पादन लागत लगातार ऊपरी स्तर पर बनी हुई है. 50 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने बिक्री के अनुपात में लागत बढ़ने की बात कही है.

निवेश और निर्यात में सकारात्मकता

सर्वेक्षण में शामिल विनिर्माण इकाइयों का संयुक्त वार्षिक कारोबार 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक है. इन इकाइयों का औसतन उत्पादन क्षमता उपयोग करीब 75 प्रतिशत है, जो क्षेत्र में टिकाऊ आर्थिक गतिविधियों का संकेत है. रिपोर्ट कहती है कि भविष्य का निवेश परिदृश्य भी सकारात्मक है. आधे से अधिक उद्योगों ने अगले छह महीनों में निवेश और विस्तार की मंशा जताई है.

समाचार विशेष

इन 'सियासी शस्त्रों' से लड़ा जाएगा चुनावी संग्राम

एनडीए-महागठबंधन के लिए कौन आएगा काम

पटना. बिहार में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है. राजनैतिक पंडितों के मुताबिक इस बार का चुनावी रण रोचक होने वाला है. पहली बार बिहार में जातियों से ऊपर उठकर चुनाव में कई दूसरे मुद्दे जोर पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी महागठबंधन दोनों ने ही अपने-अपने मुद्दे तय कर लिए हैं.

सूबे में सियासी संग्राम का शंखनाद हो चुका है. सियासतदानों ने कमर कस ली है. ऐसे में सरल शब्दों में समझ लेते हैं कि आखिर इस राज्य के मुद्दे क्या हैं? सभी

पार्टियां किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा फोकस कर करती दिख रही हैं. साथ ही यह भी जानेंगे कि इन मुद्दों का कितना असर होने वाला है?

बिहार में चुनाव से पहले हुए एसआईआर यानी मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर विपक्षी दल पहले से ही हमलावर हैं. महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने तो सूबे में वोटर अधिकार यात्र भी निकाल दी थी. इसके साथ ही बीजेपी पर चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी के आरोप भी लगाए थे. इस लिहाज से एसआईआर और वोट चोरी विपक्ष के लिए इस चुनाव में बड़ा मुद्दा होने वाला है. हालांकि यह मुद्दा वोटर्स पर उतना प्रभावशील नहीं दिखाई दे रहा है.

घुसपैठियों पर होगी तकरार- बिहार चुनाव में घुसपैठिए एक बड़ा मुद्दा हैं. चुनावी मौसम में भाजपा ने इस मुद्दे को हवा दे दी है. महागठबंधन जहां एसआईआर को निशाना बनाकर वोट बैंक जुटाने की कोशिश कर रहा है, वहीं भाजपा अवैध बांग्लादेशियों और म्यांमार से आए लोगों को घुसपैठिया बताकर बिहार की सुरक्षा का मुद्दा भी उठा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक, सभी ने अपनी हर जनसभा में इस मुद्दे को उठाया है. इसका असर दिख सकता है. बिहार के हर चुनाव में कानून-व्यवस्था एक बड़ा और गंभीर मुद्दा होता है. इस चुनाव में, महागठबंधन ने भी नीतीश कुमार की सुशासन बाबू वाली छवि को धूमिल करने के लिए कानून-व्यवस्था के मुद्दे को उठाया है. महागठबंधन का दावा है कि नीतीश कुमार के राज में हत्याएं, अपहरण और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं.

चुनावी गेमचेंजर है ये मुद्दा

एनडीए और महागठबंधन एक बार फिर बिहार की आधी आबादी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. सीएम नीतीश कुमार ने चुनाव की तारीखों से पहले ही मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना की किश्तें जारी कर दी हैं. जानकारों का मानना है कि सत्ता विरोधी लहर के बीच यह योजना गेमचेंजर साबित हो सकती है. महागठबंधन की बात करें तो वह भी महिला आरक्षण और कानून-व्यवस्था के मुद्दे उठाकर महिलाओं को लुभाने की कोशिश कर रहा है.

चिराग ने निकटस्थों को सौंपी बागडोर

समधि को बनाया चुनाव प्रभारी

पटना. बिहार चुनाव के मद्देनजर लोजपा-आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने समधी अरुण भारती को पार्टी का चुनाव प्रभारी और लोजपा-आर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को सह चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है. जिसके बाद यह अटकलें तेज हो गई हैं कि चिराग पासवान ने अपना रास्ता अलग कर लिया है!

इस संबंध में पार्टी द्वारा जारी पत्र में लिखा है कि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के आदेशानुसार, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सांसद अरुण भारती को चुनाव प्रभारी और पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को सह-चुनाव प्रभारी नियुक्त किया जाता है. पत्र में आगे कहा गया है कि पार्टी के चुनाव एवं अन्य गतिविधियों के संचालन हेतु नियुक्त प्रभारियों की सूची संबंधी परिपत्र तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है. इस निर्णय के बाद, अब लोजपा-आर की चुनावी गतिविधियों और उम्मीदवारों के चयन संबंधी निर्णय अरुण भारती और राजू तिवारी की सहमति से लिए जाएंगे.

40 सीटों की मांग कर रहे चिराग- एनडीए की सहयोगी चिराग पासवान की पार्टी ने 40 सीटों की मांग की है. लेकिन इस पर भाजपा और जदयू असहमत दिखाई दे रहे हैं. इसके अलावा यदि चिराग को मुंहमांगी सीटें मिली तो जीतन राम मांझी भी 15 सीटों को बगैर नहीं मानेंगे. वह तो अकेले 100 सीटों पर लड़ने की चेतावनी भी दे चुके हैं. अटकलें लगाई जा रही हैं कि अरुण भारती पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं. चिराग पासवान ने इस बात के संकेत दिए हैं. उन्होंने कहा कि अभी यह तय नहीं हुआ है कि वे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं. अगर पार्टी फैसला करती है, तो संभव है कि वे या कोई अन्य सांसद विधानसभा चुनाव लड़ें.

क्यों ज्यादा सीटें मांग रहे चिराग?

बिहार में लोजपा-आर का कोई विधायक नहीं है. पार्टी के पांच सांसद हैं. हाजीपुर से चिराग पासवान, जमुई से अरुण भारती, खगड़िया से राजेश वर्मा, समस्तीपुर से शांभवी चौधरी और वैशाली से वीणा देवी. चिराग की पार्टी का लोकसभा चुनाव में शत-प्रतिशत स्ट्राइक रेट रहा था. जिसके दम पर वो ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं.

विशेष | **आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल, बसपा से भाजपा में आने के संकेत**

क्या रुस्तम सिंह की होगी घर वापसी?

मुरैना. मध्यप्रदेश में पूर्व मंत्री रहे रुस्तम सिंह के एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है. राजनीतिक हलकों में यह चर्चाएं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पथ संचलन के बाद बौद्धिक कार्यक्रम के बाद तेज हुई हैं.

संघ के इस बौद्धिक कार्यक्रम में पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह अपने पुत्र राकेश सिंह के साथ शामिल हुए थे. इस दौरान पिता पुत्र लगभग एक घंटे तक सामान्य अतिथि की तरह संघ कार्यकर्ताओं तथा गणमान्य नागरिकों के बीच उपस्थित रहे. हालांकि इसे भाजपा, कांग्रेस तथा संघ से जुड़े लोग पूर्व मंत्री का व्यक्तिगत मामला बता रहे हैं. कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा को रुस्तम सिंह का पुराना घर बता रही है. हालांकि भाजपा में आने के बाद रुस्तम सिंह व उनके पुत्र राकेश सिंह से राजनैतिक रूप से कुछ भी प्रभावित न होना है. वहीं भाजपा कार्यकर्ता यह निर्णय पार्टी प्रमुख ही द्वारा लेना बताया जा रहा है.

मध्य प्रदेश शासन में उप पुलिस अधीक्षक के पद से शामिल हुए रुस्तम सिंह पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पहुंचने के बाद वर्ष 2003 में सेवानिवृत्ति ले ली थी. उस वर्ष भाजपा ने मुरैना विधानसभा क्षेत्र से उन्हें उम्मीदवार बनाया, जिसमें रुस्तम सिंह ने बसपा प्रत्याशी परशुराम मुद्गल को 5000 से अधिक मतों से पराजित किया था.

भाजपा ने वर्ष 2004 से 2008 तक चार प्रमुख विभाग खेल, खाद्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा स्वास्थ्य विभाग का मंत्री बनाया. वर्ष 2008 के चुनाव में मंत्री रहते हुए रुस्तम सिंह विधानसभा चुनाव में पराजित हो गये. इस बार बसपा प्रत्याशी परशुराम मुद्गल प्रथम तथा कांग्रेस प्रत्याशी सोबरन सिंह मावई दूसरे स्थान पर रहे. भाजपा ने इन्हें अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग आयोग का चेयरमैन बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया. वर्ष 2013 के चुनाव में तीसरी बार मुरैना विधानसभा से चुनाव मैदान में उतारा इन्होंने बसपा प्रत्याशी रामप्रकाश राजौरिया को 1700 मतों से पराजित किया. सरकार में एक बार फिर उन्हें महत्वपूर्ण विभाग का मंत्री बनाया था. चौथी बार वर्ष 2018 के चुनाव में मंत्री रहते रुस्तम सिंह एक बार फिर कांग्रेस उम्मीदवार रघुराज सिंह कंसाना से पराजित हो गये थे.

विजय को साथ लाना चाहती है भाजपा

चेन्नई. यह कमाल की बात है कि अन्ना डीएमके से तालमेल कर लेने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि तमिल फिल्मों के सुपरस्टार और अपनी पार्टी टीवीके बना कर राज्य की राजनीति में उतरे विजय को गठबंधन में शामिल किया जाए.

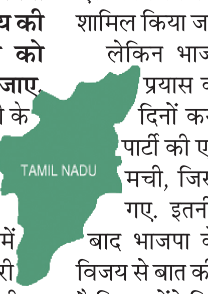

विजय खुद को मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर पेश कर रहे हैं तो दूसरी ओर अन्ना डीएमके नेता ई पलानीस्वामी किसी भी हाल में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी छोड़ने पर राजी नहीं हैं. इसी वजह से पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम पार्टी छोड़ कर गए और एनडीए से भी बाहर हुए. टीटीवी दिनाकरण की शर्त भी यही है कि पलानीस्वामी को मुख्यमंत्री का दावेदार बना कर चुनाव नहीं लड़ा जाए. पलानीस्वामी के नाम पर ही वे एनडीए छोड़ कर गए हैं. ऐसे में विजय को कैसे गठबंधन में शामिल किया जा सकता है?

लेकिन भाजपा के नेता यह प्रयास कर रहे हैं. पिछले दिनों करूर में विजय की पार्टी की एक रैली में भगदड़ मची, जिसमें 41 लोग मारे गए. इतनी बड़ी घटना के बाद भाजपा के एक बड़े नेता विजय से बात की. बताया जा रहा है कि उन्होंने विजय को एनडीए में शामिल होने का प्रस्ताव दिया. इतना ही नहीं करूर की भगदड़ के बाद भाजपा के सारे नेता वहां पहुंचे.